

उत्तराखण्ड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये अनुदान

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब, उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये [पंद्रहवें वित्त आयोग \(XV FC\) का अनुदान जारी किया है।](#)

- ये अनुदान [पंचायती राज संस्थाओं \(PRI\)](#) और [ग्रामीण स्थानीय निकायों \(RLB\)](#) को सहायता देकर ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करते हैं।

प्रमुख बडि

- XV FC अनुदान:**
 - सरकार ने उत्तराखण्ड के लिये वित्त वर्ष 2024-25 के लिये अनटाइड अनुदान की पहली कसित, 93.9643 करोड़ रुपए जारी कर दी है।
 - सरकार ने पंजाब में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 225.1707 करोड़ रुपए की अनटाइड अनुदान की पहली कसित जारी कर दी है।
 - सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिये वित्त वर्ष 2024-25 के लिये 237.1393 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट की दूसरी कसित वितरित की है।
- अनुदान आवंटन की प्रक्रिया:**
 - पंचायती राज मंत्रालय और [जल शक्ति मंत्रालय](#) (पेयजल और स्वच्छता विभाग) ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये XV FC अनुदान की सफ़ारिश करते हैं।
 - वित्त मंत्रालय इन अनुदानों को प्रतवित्तीय वर्ष दो कसितों में जारी करता है।
- XV FC अनुदान का उपयोग:**
- अप्रतिबंधित अनुदान:**
 - पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण स्थानीय निकाय इन अनुदानों का उपयोग [संवधान की ग्यारहवीं अनुसूची](#) में सूचीबद्ध 29 वषियों के अंतर्गत स्थान-वशिष्ट आवश्यकताओं के लिये कर सकते हैं।
 - इन अनुदानों का उपयोग वेतन और स्थापना लागतों के लिये नहीं किया जा सकता।
- बंधे हुए अनुदान:**
 - इन नधियों का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिये किया जाना चाहिये, जिनमें शामिल हैं:
 - स्वच्छता और [खुले में शौच से मुक्त \(ODF\) स्थिति का रखरखाव](#), जसिमें [अपशिष्ट प्रबंधन](#) और मल कीचड़ उपचार शामिल है।
 - पेयजल आपूर्ति, [वर्षा जल संचयन](#) और [जल पुनर्चरण](#)।

वित्त आयोग

- यह एक [संवधानिक निकाय](#) है, जो संवधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार **केंद्र और राज्यों** के बीच तथा राज्यों के बीच कर आय के वितरण की वधि और नियम नरिधारित करता है।
- संवधान के [अनुच्छेद 280](#) के तहत भारत के राष्ट्रपति को पाँच वर्ष के अंतराल पर या उससे पहले एक **वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक** है।
- प्रथम [वित्त आयोग](#) की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी और अब तक पंद्रह वित्त आयोग स्थापित हो चुके हैं।

15वाँ वित्त आयोग

- एन.के. सहि की अध्यक्षता में **15वें वित्त आयोग** का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को **योजना आयोग की समाप्ति और वस्तु एवं सेवा कर (GST)** लागू होने की पृष्ठभूमि में किया गया था।
- नवंबर 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **15वें वित्त आयोग** को पहले वित्त वर्ष 2020-21 के लिये अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिये अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिये इसके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/grants-for-rural-local-bodies-in-uttarakhand>

